

Daily Current Affairs 27/08/2021

1. वित्त मंत्री ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक सुधार एजेंडा – ईज़ 4.0 के चौथे संस्करण का अनावरण किया

EASE 4.0: Key initiatives

<p style="text-align: center; color: blue;">Smart Lending</p> <ul style="list-style-type: none">  Dial-a-loan for doorstep facilitation  Credit@click: End-to-end digital retail and MSME lending for New to bank customers  Analytics-based credit offers 	<p style="text-align: center; color: blue;">24*7 banking with resilient technology</p> <ul style="list-style-type: none">  Deeper penetration of Mobile & Internet banking  Cloud-based IT systems and improved cyber resilience  Process automation
<p style="text-align: center; color: blue;">Data-enabled agricultural financing</p> <ul style="list-style-type: none">  Dial-a-loan for Agri loans  Partnerships with AgriTechs for data exchange  Automated processing and sanctioning 	<p style="text-align: center; color: blue;">Collaborating with financial ecosystem</p> <ul style="list-style-type: none">  Digital payments in semi-urban and rural areas  At scale delivery of doorstep banking services  Co-lending with NBFCs

चर्चा में क्यों?

- केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2021-22 के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (PSB) सुधार एजेंडा 'ईज़ 4.0' के चौथे संस्करण का अनावरण किया।
- उन्होंने 2020-21 के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक सुधार एजेंडा ईज़ 3.0 की वार्षिक रिपोर्ट का भी अनावरण किया और ईज़ 3.0 बैंकिंग रिफॉर्मर्स इंडेक्स पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले बैंकों को सम्मानित करने के लिए पुरस्कार समारोह में भाग लिया।

प्रमुख बिंदु

ईज़ 3.0 पुरस्कार विजेता:

- स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने ईज़ इंडेक्स के आधार पर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक सुधार ईज़ 3.0 के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले बैंकों का पुरस्कार जीता है।

ईज़ 4.0 के बारे में:

- ईज़ 4.0 या एन्हांस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस - PSB के लिए एक सामान्य सुधार एजेंडा जिसका उद्देश्य स्वच्छ और स्मार्ट बैंकिंग को संस्थागत बनाना है।
- इसका उद्देश्य ग्राहक-केंद्रित डिजिटल परिवर्तन के एजेंडे को आगे बढ़ाना और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के काम करने के तरीकों में डिजिटल और डेटा को गहराई से जोड़ना है।

प्रमुख पहल:

- स्मार्ट लैन्डिंग
- लचीली तकनीक के साथ चौबीसों घंटे बैंकिंग
- डेटा सक्षम कृषि वित्तपोषण
- वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र के साथ सहयोग

ईज़ एजेंडा के बारे में:

- इसे जनवरी 2018 में सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSB) द्वारा संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया था।

विभिन्न चरण:

- **ईज़ 1.0** रिपोर्ट ने पारदर्शी रूप से गैर-निष्पादित आस्तियों के समाधान में PSB के प्रदर्शन में महत्वपूर्ण सुधार दिखाया।
- **ईज़ 2.0** को ईज़ 1.0 की नींव पर बनाया गया था और सुधार यात्रा को अपरिवर्तनीय बनाने, प्रक्रियाओं और प्रणालियों को मजबूत करने और परिणामों को चलाने के लिए नए सुधार कार्य बिंदु पेश किए।
- **ईज़ 3.0** प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए सभी ग्राहक अनुभवों में बैंकिंग कार्य को आसान बनाने का प्रयास करता है।
- **ईज़ रिफॉर्मर्स इंडेक्स:** इंडेक्स प्रत्येक PSB के प्रदर्शन को मापता है। सूचकांक का उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना है।

स्रोत: PIB

2. 'सुजलम' अभियान



ODF Sustainability and Sujlam
Launch - August 25, 2021

Focus Areas of the campaign:

1. Construction of 1 million soak pits
2. Retrofitting of toilets
3. Access to toilets for new households

100 days campaign for Greywater Management and ODF Sustainability

चर्चा में क्यों?

- जल शक्ति मंत्रालय ने 'आजादी का अमृत महोत्सव' समारोह के अंतर्गत 'सुजलम', एक '100 दिवसीय अभियान' की शुरुआत की है।

प्रमुख बिंदु

- यह अभियान ग्रामीण स्तर पर अपशिष्ट जल प्रबंधन करते हुए, विशेष रूप से दस लाख सोख-गड्डों का निर्माण करके और अन्य ग्रेवॉटर प्रबंधन गतिविधियों के माध्यम से, ज्यादा से ज्यादा ODF (खुले में शौच मुक्त) प्लस गांवों का निर्माण करेगा।
- अभियान जल निकायों के स्थायी प्रबंधन में सहायता करेगा।
- इसके अलावा, इस अभियान के माध्यम से सामुदायिक भागीदारी के द्वारा SBMG फेज II की गतिविधियों को तीव्रता प्राप्त होगी और इससे ODF-प्लस गतिविधियों के बारे में जागरूकता को बढ़ावा मिलेगा।
- इस अभियान में SBMG फेज I के दौरान प्राप्त किए गए जागरूकता और व्यवहार परिवर्तन वाले मंच का उपयोग किया जाएगा और दृश्य स्वच्छता की प्राप्ति के साथ-साथ इसकी निरंतरता सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

स्वच्छ भारत मिशन (SBM) के बारे में:

- SBM भारत सरकार द्वारा 2014 में खुले में शौच को खत्म करने और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार करने के लिए शुरू किया गया एक देशव्यापी अभियान है।
- SBM का पहला चरण अक्टूबर 2019 तक चला। दूसरे चरण को 2020-21 और 2024-25 के बीच लागू किया जा रहा है।
- मिशन को दो में विभाजित किया गया था: ग्रामीण (SBM-G) और शहरी (SBM-U)

स्रोत: PIB

3. फोरम फॉर डीकार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट



चर्चा में क्यों?

- NITI आयोग और वर्ल्ड रिसोर्सज इंस्टीट्यूट (WRI), इंडिया ने संयुक्त रूप से भारत में 'फोरम फॉर डीकार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट' शुरू किया।
- फोरम NDC-ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव फॉर एशिया

(NDC-TIA) परियोजना का एक हिस्सा है।

प्रमुख बिंदु

NDC-TIA परियोजना के बारे में:

- NDC ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव फोर एशिया (TIA 2020-2023) सात संगठनों का एक संयुक्त कार्यक्रम है जो चीन, भारत और वियतनाम को अपने-अपने देशों में परिवहन क्षेत्र में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम करने के उद्देश्य से एक व्यापक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए अपने साथ जोड़ेगा।
- यह परियोजना इंटरनेशनल क्लाइमेट इनीशियेटिव (IKI) का हिस्सा है।
- NITI आयोग परियोजना के भारत घटक के लिए कार्यान्वयन भागीदार है।

उद्देश्य:

- इस परियोजना का उद्देश्य (दो डिग्री से नीचे के मार्ग के अनुरूप) एशिया में ग्रीन हाउस गैस (GHG) उत्सर्जन (परिवहन क्षेत्र) के चरम स्तर को नीचे लाना है। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की वजह से संकुलन और वायु प्रदूषण जैसी समस्याएं होती हैं।

आवश्यकता:

- भारत में एक विशाल और विविध परिवहन क्षेत्र है, जो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करने वाला तीसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है।
- इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी (IEA), 2020; पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, 2018 के डेटा से पता चलता है कि परिवहन क्षेत्र में शामिल सड़क परिवहन, कार्बन डाइऑक्साइड के कुल उत्सर्जन में 90% से अधिक का योगदान देता है।

संबंधित पहल:

- FAME योजना (राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन योजना का हिस्सा)
- PLI योजना के तहत प्रोत्साहन
- अक्षय मोटर वाहन उद्योग

स्रोत: PIB

4. 37वीं प्रगति बैठक



चर्चा में क्यों?

- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने केंद्र और राज्य सरकारों से संबंधित ICT आधारित मल्टी-मॉडल प्लेटफॉर्म - प्रगति (प्रो-एक्टिव गवर्नेंस एंड

टाइमली इम्प्लीमेंटेशन) के 37वें संस्करण की बैठक की अध्यक्षता की।

- बैठक में कार्यसूची के नौ मदों की समीक्षा की गई, जिनमें आठ परियोजनाएं और एक योजना शामिल थी।
- 14 राज्यों से संबंधित इन 8 परियोजनाओं की संचयी लागत 1,26,000 करोड़ रुपये है।
- उन्होंने 'वन नेशन-वन राशन कार्ड (ONORC) योजना की समीक्षा की।

प्रमुख बिंदु

प्रगति के बारे में:

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में बहुउद्देश्यीय और बहु-मोडल मंच प्रगति (प्रो-एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन) लॉन्च किया था।
- प्रगति एक अनूठा एकीकृत और संवादात्मक मंच है।
- मंच का उद्देश्य आम आदमी की शिकायतों को दूर करना है, और साथ ही साथ भारत सरकार के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों और परियोजनाओं के साथ-साथ राज्य सरकारों द्वारा ध्वजांकित परियोजनाओं की निगरानी और समीक्षा करना है।
- यह एक त्रिस्तरीय प्रणाली है (PMO, केंद्र सरकार के सचिव और राज्यों के मुख्य सचिव)।
- इस प्रणाली को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) की मदद से PMO टीम द्वारा इन-हाउस डिजाइन किया गया है।
- **नोट:** पिछली 36 प्रगति बैठकों में, 13.78 लाख करोड़ रुपये की कुल लागत वाली 292 परियोजनाओं की समीक्षा की गई।

स्रोत: PIB

5. के जे अल्फोंस की किताब 'एक्सेलरेटिंग इंडिया: 7 इयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट'



करने का सराहनीय प्रयास किया है।

- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पूर्व केंद्रीय मंत्री के जे अल्फोंस ने अपनी पुस्तक 'एक्सेलरेटिंग इंडिया: 7 इयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट' भेंट की।
- प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने अपनी पुस्तक 'एक्सेलरेटिंग इंडिया' में भारत की सुधार यात्रा के विभिन्न पहलुओं को समाहित

नोट:

- हाल ही में उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने उप-राष्ट्रपति निवास में इस पुस्तक का विमोचन किया था।
- के जे अल्फॉस इस किताब के संपादक थे। भारतीय शासन के विभिन्न क्षेत्रों पर इस पुस्तक में 28 प्रसिद्ध लेखकों ने 25 निबंधों का योगदान दिया।

स्रोत: PIB

6. हिसार हवाई अड्डे का नाम बदलकर महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रखा गया

**चर्चा में क्यों?**

- हरियाणा के मुख्यमंत्री, मनोहर लाल खट्टर ने हिसार हवाई अड्डे का नाम बदलकर महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा (MAIA) करने की घोषणा की।

प्रमुख बिंदु

- 27 सितंबर, 2018 को हिसार हवाई अड्डा हरियाणा का पहला DGCA लाइसेंस प्राप्त सार्वजनिक हवाई अड्डा बन गया।
- मार्च 2024 तक हिसार हवाई अड्डे को अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में बदलने के लिए वर्तमान में उन्नयन किया जा रहा है।

स्रोत: TOI

7. फिल्म निर्माता प्रदीप गुहा का निधन



- फिल्म निर्माता और प्रसिद्ध मीडिया हस्ती प्रदीप गुहा का निधन हो गया।
- प्रदीप गुहा ने ऋतिक रोशन और करिश्मा कपूर-स्टारर "फिजा" के साथ-साथ 2008 की फिल्म "फिर कभी" का निर्माण किया था।

- उन्होंने लगभग 30 वर्षों तक टाइम्स समूह के साथ काम किया और कंपनी में अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। उन्होंने जी एंटरटेनमेंट के CEO के रूप में भी काम किया

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

Gradeup